

क्षेत्रीय असंतुलन

* 394. श्री निरंजन वर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में हैदराबाद में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि केन्द्र क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कदम उठायेगा; और

(ख) यदि हा तो मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन और गरीबी को देखते हुए मध्य प्रदेश के वास्तविक निवासियों को अखिल भारतीय सवाओं में स्थान दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सुविधायें प्रदान किये जाने का विचार है ?

† [REGIONAL IMBALANCES

*394. SHRI NIRANJAN VARMA: Will the Minister of PLANNING/ योजना मंत्री be pleased to state:

(a) whether he made a statement recently at Hyderabad to the effect that the Centre would take steps to remove regional imbalances, and

(b) if so, the facilities that are being contemplated by the Central Government for the bona fide residents of Madhya Pradesh for their entry into the All India services keeping in view the backwardness and poverty in Madhya Pradesh?]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) हैदराबाद में 12 सितम्बर, 1971 को "संतुलित क्षेत्रीय विकास" सम्बन्धी कर्मशाला के उद्घाटन भाषण में मंत्री महोदय ने कहा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों तथा विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली अत्यधिक विषमताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट नीति सम्बन्धी उपाय अपनाए जाय। यह सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व हीं अपेक्षाओं में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि संतुलित विकास के मामले पर विचार करते समय योजना आयोग ऊपर बताई गई असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर समुचित ध्यान देना है।

(ख) संविधान का अनुच्छेद 16 जन्मस्थान अथवा आवास के आधार पर सार्वजनिक नौकरियों में भेदभाव बर्तने की मनाही करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने का इरादा नहीं है।

[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING/ योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI MOHAN DHARIA): (a) In an inaugural address at the Workshop on "Balanced Regional Development" at Hyderabad on the 12th September, 1971, the Minister stated that to evolve specific policy measures so as to prevent large disparities arising as among classes and among regions in the process of economic development, was one of the requirements of social and political stability. He further stated that in considering issues of balanced growth, the Planning Commission takes due care of the need for preventing the aforesaid disparities.

(b) Article 16 of the Constitution prohibits discrimination in the matter of public employment on grounds of place of birth or of residence. In view of this, no such facilities are contemplated]

COMMISSION TO REVIEW THE FUNCTIONING OF PUBLIC SECTOR

*395. SHRI SITARAM JAIPURIA: Will the Minister of PLANNING/ योजना मंत्री be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a high-powered Commission to review the functioning of the Public Sector with particular reference to go into the criteria adopted in choosing locations for new units, inter-relationship between the Public and Private Sectors,

(b) if so, the details thereof, and

(c) the time by when the Commission is likely to be set up and what will be its terms of reference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING/ योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI MOHAN DHARIA): (a) to (c) It has been decided to set up a Steering Group to undertake a review of the